प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00 बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंचायतों में पौधरोपण करने और उसके सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए सरकार महिला मंडलों का सहयोग लेगी और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण के बाद पौधों का सर्वाइवल रेट 50 से 60 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार पौधरोपण कार्य में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों में पौधरोपण में 60 प्रतिशत फलदार पौधों को लगाया जाएगा और पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए सरकार वन मित्रों की भर्ती करने जा रही है। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 जुलाई 2024 तक गौ तस्करी के 9 मामले दर्ज हुए है। इन मामलों में दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार करना सबसे आसान था, इसलिए सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मंडी के बल्ह में भी हवाई अड्डा स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी हवाई अड्डे के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा एक हजार करोड़ रुपये के आवंटन को केंद्र द्वारा कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बल्ह हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए एएआई को केवल एक करोड़ रुपये की इक्विटी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 सौ करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परियोजना के लिए अभी तक एडीबी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला को पर्यटन राजधानी घोषित करने की घोषणा कांगड़ा जिले के लोगों को लुभाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा बंद कर दी गई है और हवाई रोपवे स्थापित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। विपक्ष के नेता की आशंकाओं को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा और रक्कड़ हेलीपोर्ट के लिए 13–13 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री वक्तव्य

प्रदेश में कर्मचारियों को इस माह वेतन 5 सितंबर को, जबकि पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह व्यवस्था परिवर्तन वित्तीय अनुशासन लाने के लिए किया गया है और इससे सरकार को हर माह तीन करोड़ रुपए जबकि साल में 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाने व वित्तीय स्थिति में सुधार और राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने व 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने के लिए भविष्य में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन का यह भुगतान बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वे अपने संसाधनों से इस खर्च को पूरा करते हैं। हालांकि, सरकार कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों की ईएमआई का समय पर भुगतान करने की दलीलों पर विचार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के तहत व्यय को राजस्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाए जा रहे धन को बचाया जा सके।

जीरो आवर

प्रदेश विधानसभा में जीरो आवर आरंभ करने के मुद्दे पर आज सदन में खूब तकरार हुई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जहां जीरो आवर तुरंत शुरू करने की पैरवी की, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह कहते हुए जीरो आवर तुरंत शुरू करने का विरोध किया कि सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है और जीरो आवर आरंभ करने से पहले इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और इसकी एसओपी तय होनी चाहिए। विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जीरो आवर का मुद्दा उठाया और कहा कि यह अच्छी परंपरा है, लेकिन इसमें सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर संस्था की अपनी गरिमा है और लोकतंत्र इसी मायने में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यहां पर जीरो आवर के लिए एसओपी बनानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो आवर को लेकर सरकार तैयार नहीं है।

उज्ज्वल ऊना'

ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने जिले को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज 'उज्ज्वल ऊना' मुहिम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए चार स्तरीय निस्तारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पंचायत में घरों से कचरा एकत्रित कर उसे ग्राम पंचायत स्तर पर बने सेग्रीगेशन यूनिट में लाया जाएगा और उसका उचित निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद, कई पंचायतों के कचरे को क्लस्टर स्तर पर बने माइक्रो सेग्रीगेशन यूनिट में भेजा जाएगा। उपायुक्त ने सभी विकास खंड अधिकारियों को मुहिम के सफल क्रियान्वयन के निर्देश देते

हुए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह मुहिम जिले को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने और स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने में प्रभावी होगी। उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता बदलाव लाने और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

———————————